रिविजनल सिविल

न्यायमूर्ति सी जी सूरी के समक्ष

राम सरूप, ***याचिकाएं।***

बनाम

हार्फुल और अन्य, - ***उत्तरदाता।***

1971 का सिविल संशोधन संख्या 891

30 अगस्त, 1971

*उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (*1873 का आठवां) - धारा 30-ए से 30-एफएफ और 30-जी - *जल-मार्ग के विध्वंस की धमकी वाली गलती को रोकने के लिए दायर सिविल मुकदमा - इस तरह के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र* - चाहे धारा 30-जी के तहत निषिद्ध *हो ।.....*

माना जाता है कि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 30-ए से 30-एफएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है , जो यह बताता है कि एक पक्ष के पास अधिनियम के तहत कोई उपाय है जहां वह जल-मार्ग के विध्वंस की धमकी को रोकने की कोशिश कर रहा है। नहर प्राधिकरण एक गलती को ठीक कर सकते हैं जो पहले ही किया जा चुका है और यह आवश्यक नहीं है कि एक पार्टी को हमेशा तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि नुकसान नहीं हो जाता। सूखे के मौसम के दौरान, नहर प्राधिकारियों को कार्रवाई में लगने वाला समय फसल को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता

है और चूंकि अधिनियम में खतरे की रोकथाम के लिए कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए निवारक उपाय लागू करने के लिए पीड़ित पक्ष के न्यायालय आने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए जहां जल-मार्ग के विध्वंस की धमकी को रोकने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 30-जी के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं है।

(पैरा 5)

सी.पी.सी. की धारा 115 *के तहत श्री वी.डी.*

अग्रवाल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद, दिनांक 29 जून, 1971 को श्री सी. डी. वशिष्ठ, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, जींद, दिनांक 1 जून, 1971 की पुष्टि करते हुए।

11 मार्च, 1971 के एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश की पुष्टि *करते हुए मामले का गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय आने तक।*

सिविल विविध सं. 1971 *का* 5552 :-

धारा 151 *सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रार्थना करता है कि संशोधन का अंतिम निर्णय लंबित है,* आक्षेपित *^ का संचालन*

और कार्यान्वयन

नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से *सुरिंदर सरूप, एडवोकेट।*

पूरन चंद, वकील, *उत्तरदाताओं के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति सूरी- (1) यह पुनरीक्षण याचिका जींद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 और धारा 151 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश की अपील पर पुष्टि की है, जिसमें याचिकाकर्ता और उसके बेटों को एक वाटरकोर्स (*खल*) को बहाल करने का निर्देश दिया गया था, जिसे उनके खिलाफ स्थगन आदेश पारित करने के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। कहा जाता है कि वादी-प्रतिवादी के आवेदन पर याचिकाकर्ता और उसके बेटों के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए अलग से कार्यवाही शुरू की गई है।

(2) मुकदमा 10 मार्च, 1971 को दायर किया गया था और ट्रायल कोर्ट ने वादी-प्रतिवादी के आवेदन पर 11 मार्च, 1971 को याचिकाकर्ता और *उसके बेटों (मुकदमे में प्रतिवादियों) के खिलाफ एकपक्षीय* स्थगन आदेश दिया था। वाद में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने पहले भी खल को ध्वस्त कर दिया था और नहर अधिकारियों ने खल को बहाल कर दिया था । कहा जाता है कि प्रतिवादी उस वाटरकोर्स को ध्वस्त करने के लिए फिर से धमकी दे रहे थे। इसलिए यह एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करता है ताकि खतरे वाली गलती को रोका जा सके।

(3) न्यायालय द्वारा नियुक्त एक स्थानीय आयुक्त ने 15 फरवरी, 1971 को घटनास्थल का निरीक्षण किया था और रिपोर्ट दी थी कि विवादित जलमार्ग उस स्थान पर मौजूद था। हालांकि, एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित होने के कुछ दिनों बाद उनके जलमार्ग को ध्वस्त कर दिया गया था । इसलिए, नीचे दिए गए दो न्यायालय ों ने जलमार्ग की बहाली का निर्देश देने और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान और स्थगन आदेश पारित करने के बाद हुए एक मनमाने कृत्य को रद्द करने का निर्देश देना पूरी तरह से उचित था। इसलिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है यदि नीचे दिए गए दो न्यायालयों ने

प्रतिवादियों के खिलाफ एक अनिवार्य आदेश दिया था, जिसमें उन्हें खल के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया गया था /

(4) याचिकाकर्ता के वकील श्री सुरिंदर सरूप ने उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 30-एफएफ की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। संभागीय नहर अधिकारी पीड़ित पक्ष के आवेदन पर एक जलमार्ग की बहाली का निर्देश दे सकता है, लेकिन उसे धारा 30-एफएफ की उप-धारा (2) के तहत संबंधित व्यक्ति पर लिखित में नोटिस जारी करने के बाद जांच करनी होगी। यदि वह व्यक्ति आदेशों को पूरा करने में विफल रहता है, तो डिवीजनल नहर अधिकारी गलती पर पार्टी की कीमत पर वाटरकोर्स को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सकता है और इन लागतों को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। संभागीय नहर अधिकारी के आदेशों से अधीक्षण नहर अधिकारी के पास अपील की जाती है। श्री सुरिंदर सरूप का तर्क है कि प्रतिवादी को इस धारा के तहत अपने उपायों का सहारा लेना चाहिए था और उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 30-जी के प्रावधानों के मद्देनजर सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक है। यह खंड निम्नानुसार चलता है:-

> "30-G. इस अधिनियम या अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद, किसी भी सिविल कोर्ट को धारा 30-ए से 30-एफएफ के तहत आने वाले मामलों से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।

(5) हालांकि, धारा 30-ए से 30-एफएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे सकता है कि किसी पार्टी के पास इस अधिनियम के तहत कोई उपाय है जहां वह खतरे वाली गलती को रोकने की कोशिश कर रहा है। नहर प्राधिकरण पहले ही की जा चुकी गलती को ठीक कर सकते हैं और ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रतिवादी को पिछले

अवसर पर भी उन उपायों का लाभ उठाना पड़ा हो। याचिकाकर्ता के आचरण ने उसके मन में एक आशंका पैदा कर दी थी कि वही गलत फिर से होने जा रहा है और इसलिए, उसने उस धमकी को गलत होने से रोकने के लिए यह मुकदमा दायर किया था। बाद की घटनाओं से यह भी पता चला है कि उनकी आशंकाएं बिना किसी ठोस आधार के नहीं थीं। यह जरूरी नहीं है कि पार्टी को हमेशा तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि नुकसान नहीं हो जाता। सूखे के मौसम के दौरान, नहर अधिकारियों को अलग करने में लगने वाला समय फसल को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है और चूंकि इस तरह के खतरे की रोकथाम के लिए उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 में कोई प्रभावी उपाय प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए वादी को निवारक उपाय लागू करने के लिए अदालत आने पर कोई रोक नहीं थी। धारा 30-एफएफ खतरे वाली चोट की रोकथाम के लिए प्रावधान नहीं करती है। यह केवल एक उपाय प्रदान करता है जहां चोट पहले से ही लगी थी। इसलिए, धारा 30-एफएफ उस उपाय के लिए केवल एक खराब विकल्प प्रदान करती है जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर मांगा गया था जब मुकदमा दायर किया गया था।

(6) मुझे हस्तक्षेप करने और मुआवज़ा के साथ संशोधन याचिका को खारिज करने का कोई आधार नहीं दिखता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के

उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा